HINDUSTAN, Delhi, 2.10.2024
Page No. 5, Size:(5.93)cms X (10.97)cms.

टिल्लू ताजपुरिया केस में डीएम-डीसीपी को नोटिस

सख्ती

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आधी-अधूरी रिपोर्ट भेजने पर नाराजगी जताई

नई दिल्ली/रामपुर। तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। आधी-अधूरी रिपोर्ट भेजने से नाराज आयोग ने दिल्ली के डीजी जेल, डीएम और डीसीपी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ आयोग में दाखिल करें अन्यथा उनके खिलाफ आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा।

आयोग ने यह कार्रवाई रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के उस पत्र पर की है, जिसमें उन्होंने आयोग से अपील की थी कि आयोग से बार-बार रिमाइंडर के बाद भी संबंधित अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं और साक्ष्य आयोग में पेश नहीं कर रहे हैं। रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल देश की अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन वहां आए दिन गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं। आरोप लगाया कि यह सब जेल अधीक्षक और जेल प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव है। इनकी भूमिका संदिग्ध है। इसी के चलते दो मई को टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या कर दी गई। इसके सीसीटीवी फुटेज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया था।

आयोग ने दानिश खां की शिकायत पर केस दर्ज कर राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली के डीएम, राजौरी गार्डन के डीसीपी और डीजी जेल से अब तक की कार्रवाई, जांच, पीएम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि के साथ छह सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन, रिपोर्ट आधी-अधूरी भेजी गई। जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग में दोबारा पत्र प्रेषित कर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है, इस पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में धारा 13 के तहत पूछताछ और क्रिमनल केस दर्ज करने की चेतावनी जारी की है।

JANSATTA, Delhi, 2.10.2024
Page No. 22, Size:(5.46)cms X (9.87)cms.

मानवाधिकार आयोग ने बिहार के डीजीपी को भेजा नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

बिहार के कैमूर जिले में सांप के काटने से हुई मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। सांप के काटने के बावजूद पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में रखा और दो हजार रुपए की घूस मांगी। बामुश्किल वह सात सौ रुपए जुटा पाया। उन्हें लेने के बाद ही अस्पताल जाने दिया। जहां इलाज में देरी के कारण उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। आयोग ने घटना की मीडिया में आई खबरों का खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक से दो हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा है।

पीड़ित 26 सितंबर की रात अपने खेत में पानी चला रहा था। तभी उसे सांप ने काट लिया। इसके बाद पीड़ा के कारण वह खेत से गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन बीच में ही गश्त कर रहे पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और उससे सवाल-जवाब करने लगे। उसने उन्हें बताया भी कि उसे सांप ने काट लिया है और वह अपने घर जा रहा है।

पर पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और शर्त रखी कि दो हजार रुपए दिए बिना वे उसे एक कदम भी नहीं बढ़ाने देंगे।खबर के मुताबिक पुलिस वाले उसके साथ उसके घर भी पहुंच गए, पर घर में पैसे नहीं थे। इस पर पीड़ित ने अपने बड़े भाई को बुलाया पर उसकी जेब भी खाली थी। बमुश्किल उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके पुलिस वालों को सात सौ रुपए दिए तब उन्हें छोड़ा गया।

सांप काटने से पीड़ित की हुई मौत का मामला
पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में रखा और दो हजार रुपए की घूस मांगी।

इस चक्कर में इतना वक्त बीत गया कि उसकी जान नहीं बच पाई। आयोग ने पाया कि पीड़ित को अगर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। आयोग ने इसे पीड़ित के मानवाधिकार हनन और बिहार पुलिस के अधिकार के दुरुपयोग का मामला माना है। आयोग ने कैमूर के जिला कलेक्टर से भी पूछा है कि पीड़ित के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गई है या नहीं।

BSP News: स्टाफ को 8 घंटे की ड्यूटी में नहीं मिल रहा ब्रेक, गृहमंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत...

https://www.patrika.com/bhilai-news/staff-is-not-getting-a-break-for-8-hours-of-duty-19030503

BSP News: बीएसपी में कर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से एजेंसी के पायलट और स्टाफ न तो शौचालय जा पा रहे हैं और न उनको कैंटीन जाकर चाय पीने के लिए ब्रेक मिल रहा है।

भिलाई•Oct 01, 2024 / 12:49 pm•

BSP News: भिलाई स्टील प्लांट में लोको चालकों और शंटिंग स्टाफ के अधिकारों का हनन हो रहा है। इन कर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से एजेंसी के पायलट और स्टाफ न तो शौचालय जा पा रहे हैं और न उनको कैंटीन जाकर चाय पीने के लिए ब्रेक मिल रहा है। इससे परेशान होकर कर्मियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और देश के गृहमंत्री अमित शाह से शिकायत की है।

भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 4, 5, 6, 7, 8 हैं। यहां लोको चालक व शंटिंग स्टाफ लोको इंजन से हॉट मेटल समेत अन्य सामग्री इधर से उधर करते हैं। इन कर्मियों से 3 अलग-अलग शिफ्ट में कार्य लिया जाता है। इसके अलावा टीएण्डडी कंट्रोल, स्टील स्टेशन, पीपीयार्ड, ओपन अर्थ स्टेशन में भी वे काम कर रहे हैं। बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 1 से 7 वाले राह में जो लोको दौड़ रही है, उसमें पायलट के तौर पर बीएसपी के नियमित कर्मचारी मौजूद होते हैं। वहीं यहां शंटिंग स्टाफ ठेका एजेंसी से दिया जाता है।

सेफ्टी के नाम पर किया जा रहा प्रताड़ित

आयोग और गृहमंत्री को लिखे पत्र में बताया गया है कि भिलाई स्टील प्लांट में सेफ्टी विभाग के नाम पर कुछ कर्मचारी दिन और रात में किसी भी वक्त आते हैं। लोको में चालक और मौके पर शंटिंग स्टाफ नजर नहीं आता है, तब वे फोटो लेकर तुरंत अधिकारी को भेज देता है। इस तरह से माह में कम से कम 20 शिकायत की जाती है। इसके बाद अधिकारी बुलाकर काम से हटाने, वेतन काटने की बात कहकर फटकार लगाते हैं।

अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन

अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें सम्मानजनक जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ठेका श्रमिकों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जो इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। धारा 63लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह नियमों के विपरीत है।

एक चालक से करवाया जा रहा काम

यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अनुच्छेद 23 यह अनुच्छेद श्रमिकों को सुरक्षित और उचित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने का अधिकार देता है। ठेका श्रमिकों को 8 घंटे तक बिना किसी ब्रेक या उचित सुरक्षा उपायों के काम कराया जा रहा है। जो यूडीएचआर के इस अनुच्छेद का उल्लंघन है।

Dhar kids electrocution: NHRC seeks report within 2 wks

https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/tragic-electrocution-of-dhar-students-nhrc-demands-immediate-investigation/articleshow/113855706.cms

TNN | Oct 1, 2024, 07.15 PM IST

Indore: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday took suo motu cognizance of the deaths of two scheduled tribe students due to electrocution while cleaning a water tank in a govt hostel of Dhar on Sept 25.

The commission has issued notices to chief secretary and director general of police, govt of Madhya Pradesh, seeking a detailed report within two weeks. They have been asked to include status of the police investigation and details of the compensation, if any, provided to the bereaved families of both the victims, in the report.

"As per the media report published on Sept 26, 2024, the students came in contact with a wire connected to a water pump inside the tank while cleaning it. They were found lying inside the tank by villagers who reportedly informed the hostel authorities," a press release issued by NHRC reads.

"The media reports clearly indicate the insensitive behaviour of the hostel authorities in engaging young boys in such a hazardous task, resulting in their death," states the press release.

The commission has observed that if the contents of the media report are true, it raises a serious issue of violation of human rights of the victim students.

Government portals should provide mother s name instead of father s: NHRC

https://www.thehindu.com/news/national/government-portals-should-provide-mothers-name-instead-of-fathers-nhrc/article68706473.ece

A discussion, attended by officials from Ministries, NGOs and teachers, concluded that there is an urgent need for empirical data on challenges faced by children of sex workers and marginalised groups

Published - October 01, 2024 09:36 pm IST - New Delhi

Government record portals should mandatorily provide the mother's name instead of the father's, suggested the National Human Rights Commission (NHRC) while concluding an open house discussion on human rights of children of sex workers and marginalised communities.

The discussion, attended by senior officials from Ministries concerned, NGOs and teachers, concluded that there is an urgent need for empirical data, necessitating research focused on the wide range of challenges faced by the children of this group. There should be an impact assessment of various government schemes, it suggested.

"The government portals should mandatorily provide the mother's name instead of the father's. The option to give the name of the guardian should be added," the NHRC said.

S. Vijaya Bharathi, acting chairperson, NHRC, emphasised the need for protecting the rights of children of sex workers and marginalised communities and said that despite several safeguarding measures, many children still face stigma, poverty, and have limited access to essential resources, which perpetuate cycles of vulnerability and discrimination.

Bharat Lal, secretary general, NHRC, underscored the importance of fundamental facilities, such as education and healthcare, for these vulnerable children. He emphasised the necessity of prioritising children's health and nutrition while acknowledging the government's ongoing initiatives in this regard.

The suggestions by the NHRC also include need for proper documentation, such as Aadhaar cards, to be made accessible to sex workers and their children to facilitate their admissions to schools, and the processes of obtaining their necessary identification and documentation should be streamlined.

The discussion concluded that proper implementation of existing schemes and laws designed to protect the rights of such children is ensured. The commission stressed that there is a crucial need for the employment and active engagement of trained social workers to foster trust and facilitate access to necessary services for children from this group.

India News | NHRC Notice to Bihar Govt over Death of Man detained by Policemen After Snake Bite

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-notice-to-bihar-govt-over-death-of-man-detained-by-policemen-after-snake-bite-6311085.html

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The NHRC on Tuesday said it has issued a notice to the Bihar police chief over reports that a man bitten by a snake lost his life as he was allegedly detained and not allowed to rush to a hospital by some policemen in Kaimur district.

New Delhi, Oct 1 (PTI) The NHRC on Tuesday said it has issued a notice to the Bihar police chief over reports that a man bitten by a snake lost his life as he was allegedly detained and not allowed to rush to a hospital by some policemen in Kaimur district.The policemen had reportedly demanded Rs 2,000 in "bribe", forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700 to manage his release, but by that time the man had already lost considerable time in getting critical treatment, the rights panel said in a statement.

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim due to the "abuse of power" by police personnel who were supposed to take the man to the hospital immediately to save his life.The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that a man bitten by a snake has lost his life as he was detained and not allowed to rush to the hospital for treatment by some policemen despite his repeated request in Kaimur district".

It has issued a notice to the director general of police, government of Bihar, seeking a detailed report within two weeks. It is expected to include the status of the police investigation as well as action taken against the errant police personnel, the statement said.The Commission has also asked the district magistrate of Kaimur to inform whether any compensation has been paid to the next of kin of the deceased person, it said.According to the media report, carried on September 27, the man was bitten by a snake while he was irrigating the crops on the night on September 26.After this, he started running from the fields in a restless state towards his village. Meanwhile, a patrolling police team stopped and started interrogating him.The man told them that he has been bitten by a snake and was running to reach home. The police personnel did not believe him and asked him to pay Rs 2,000 otherwise, he would not be allowed to move, it added.According to the news report, the police personnel accompanied him to

his house but there was no money available at home. The man then called his elder brother but he also had no money with him.Somehow, Rs 700 was arranged and given to the police personnel. But by that time, reportedly, considerable time had been lost to get the snake bite victim treatment to save his life, the statement said.

Jamshedpur Mgm Hospital – एमजी एम अस्पता ल की गा यनी विभाग की समस्या ओं से अवगत हुई रा ष्ट्री य मा नवा धिकार आयो ग की स्पेशल रेपौ टियर, डॉ क्टरों ने सा फ-सफाई, बेड व सुरक्षा को लेकर कही यह बा तें

https://sharpbharat.com/information/jamshedpur-mgm-hospital-national-human-rights-commissions-special-rapporteur-became-aware-of-the-problems-of-the-gynecology-department/457880/

जमशेदपुर : जमशेदपुर के एमजी एम अस्पता ल के गा यनी वि भा ग का नि री क्षण के दौरा न वि भा ग के डॉ क्टरों ने रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग के स्पेशल रैपौ टि यर सुचि त्रा सि न्हा को बता या कि एमजी एम अस्पता ल में गा यनी वि भा ग की सुरक्षा के ना म सि र्फ दो हो मगा र्ड रहते है. वह भी कि सी प्रका र की घटना हो ने पर भा ग जा ते है. वहीं जूनि यर डॉ क्टरों ने बता या कि हम लो गों को हॉ स्टल नहीं है, जि सके का रण दूसरे जगहों से आना पड़ता है. रा त ड्यूटी हो ने पर आने व जा ने में का फी परेशा नी हो ती है. इसके लि ए अगर अस्पता ल से ला ने व ले जा ने की व्यवस्था कर दे तो हम लो ग सुरक्षि त रह सकते है. वहीं एक मरी ज के सा थ पां च-पां च लो ग गा यनी वि भा ग में आ जा ते है, जि सको रो कने वा ला को ई नहीं हो ता है. हम लो गों के बो लने पर लड़ा ई करने पर उता रू हो जा ते है. इसके सा थ ही गा यनी वि भा ग के शौ चा लय की स्थि ति का फी खरा ब है. ला इट के सा थ लेबर रूम, एचडी यू में इमरजेंसी दवा तक नहीं रहती है. इसके सा थ ही वि भा ग में लगी मरी जों की लि फ्ट खरा ब है. अस्पता ल में बला त्का र से संबंधि त केस जां च के लि ए आता है व एचआइवी की जां च कि ट नहीं हो ने के का रण जां च करने में का फी परेशा नी हो ती है.

मरी ज का फि टबेक की जा नका री के लि ए रजि स्टर, मरी जों को जा नका री के पूछता छ केंद्र तक अस्पता ल में उपलब्ध नहीं है. डॉ क्टरों ने बता या कि अस्पता ल में अगर मरी ज को ब्लड व जां च करा ने की जरूरत हो ती है वह नहीं हो पा ता है. मेडि कल अस्पता ल में स्थि त ब्लड बैंक में ब्लड नहीं हो ने के का रण उन लो गों को जमशेदपुर ब्लड बैंक जा ना पड़ता है जि स मरी ज के सा थ को ई नहीं रहता है. उसके लि ए कर्मचा री को भेज कर ब्लड मां गवा ना पड़ता है, जि ससे परेशा नी हो ती है. इसके लि ए अगर हम लो गों को जा नका री रहे कि कि स ब्लड ग्रुप का कि तना ब्लड है तो का म करने में सहा यता मि लेगी . इसके लि ए एक कर्मचा री को नि युक्त करने की जरूरत है जो ब्लड के बा रें में पूरी जा नका री रखें. वहीं कई मशी न नहीं है जि ससे दि क्कत हो ती है. यहां तक मरी जों को पी ने के पा नी की व्यवस्था तक नहीं है. (नी चे भी पढे)

डॉ क्टरों ने बता या कि वि भा ग में कपड़ा बदलने के लि ए रूम तक नहीं है, जो रूम में उसमें कचरा भरा हुआ है. उसी में कपड़ा बदलते है जि ससे मरी ज को इंफेक्शन हो सकता है. इसके सा थ ही अस्पता ल का गा यनी वा र्ड 60 बेड है जि सको बढ़ा कर 100 कर दि या गया है. वहीं प्रति दि न 150 से ज्या दा महि ला एं इला ज व प्रसव के लि ए आती है जि समें प्रति दि न 20 से ज्या दा प्रसव करा या जा ता है. बेड नहीं हो ने के का रण मजबूरी में जमी न पर लेटाकर रखा जा ता है. इससे इंफेक्शन हो सकता है. वहीं सफा ई कर्मचा री के द्वारा दि न में दो बा र ही सफा ई कि या जा ता है जबकि हर समय सफा ई की जरूरत है. डॉ क्टरों ने बता या

कि पो स्ट ऑपरेटि व वा र्ड में इंफेक्शन ज्या दा है. क्योंकिक्योंकि वहां मरी ज को रखने तक की जगह नहीं है. वहीं इस वा र्ड में ऑक्सी जन, मो नि टर तक नहीं है. (नी चे भी पढ़ें)

इस्टेला इजर मशी न, रेस्ट करने की रूम, सुरक्षा चेक प्वाइंट, शौ चा लय ठी क करने की जरूरत बता यी . रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग के स्पेशल रैपौ टि यर सुचि त्रा सि न्हा को बता या कि एमजी एम अस्पता ल के गा यनी वि भा ग का नि री क्षण करने के सा थ अस्पता ल के अधी क्षक डॉ शि खा रा नी को कई बा र फो न कर बुला या गया लेकि न वे नहीं आयी . जि सपर ना रा जगी जा हि र की अस्पता ल के अधी क्षक डॉ शि खा रा नी सहि त वि भा ग के सभी डॉ क्टरों व एचओडी के सा थ बैठक की . इस दौरा न उन्हों नेन्हों नेगा यनी वा र्ड की समस्या ओं पर चर्चा की . इस पर अधी क्षक ने उनको बता या कि अभी कुछ दि न ही अधी क्षक बने हुआ है. जि तना भी समस्या है उसको दूर करने का का म कि या जा रहा है. जल्द ही इसमें का फी समस्या हो दूर कर दि या जा येगा . इसके लि ए का म हो रहा है.

NHRC Issues Notice After Snakebite Victim Dies in Police Custody

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3107516-nhrc-issues-notice-after-snakebite-victim-dies-in-police-custody

The NHRC has issued a notice to the Bihar police chief after reports surfaced that a man, bitten by a snake, died due to police detention and a bribery demand preventing him from reaching a hospital in time. The NHRC has called for a detailed report and inquiry within two weeks.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 01-10-2024 22:54 IST | Created: 01-10-2024 22:54 IST

The NHRC has issued a notice to the Bihar police chief following reports that a man, bitten by a snake, lost his life due to being detained by policemen who demanded a bribe, thereby delaying his hospital visit in Kaimur district.

The policemen allegedly demanded Rs 2,000, forcing the man to call his brother, who managed to arrange only Rs 700, delaying critical medical treatment, according to the NHRC.

The National Human Rights Commission cited that if the news reports are accurate, it signifies a severe violation of human rights due to police misconduct. The NHRC has requested a detailed report within two weeks, including the investigation's status and any action against the police personnel.

NHRC Issues Notice Over Hostel Deaths in Madhya Pradesh

https://en.themooknayak.com/education/nhrc-issues-notice-over-hostel-deaths-in-madhya-pradesh

Negligence Alleged as Hostel Staff Ordered Hazardous Task

the Mooknayak English Published on: 01 Oct 2024, 2:44 pm

New Delhi- Two students were found dead while cleaning a water tank at a government-run hostel in Dhar district of Madhya Pradesh on September 25, according to a media report. The students were allegedly asked to clean the tank by the hostel superintendent.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the news and has issued a notice to the Chief Secretary and the Director General of Police of Madhya Pradesh calling for a detailed report within two weeks. The Commission has also requested the Director General of Police to provide details on the status of the police investigation and compensation paid to the families of the victims.

The Commission has observed that the hostel authorities have acted in an insensitive manner by asking the young boys to execute such a hazardous task that resulted in their deaths. The NHRC has also raised concerns about the violation of human rights of the students.

According to the media report, the two students were found lying in the tank after coming into contact with a live wire connected to a water pump inside the tank while they were cleaning it. The villagers at the hostel notified the hostel authorities about the incident.

DECCAN HERALD, Online, 2.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to Bihar govt over death of man 'detained' by policemen after snake bite

https://www.deccanherald.com/india/bihar/nhrc-issues-notice-to-bihar-govt-over-death-of-man-detained-by-policemen-after-snake-bite-3215871

The policemen had reportedly demanded Rs 2,000 in 'bribe', forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700 to manage his release, but by that time the man had already lost considerable time in getting critical treatment, the rights panel said in a statement.

Last Updated : 02 October 2024, 03:12 IST

The policemen had reportedly demanded Rs 2,000 in 'bribe', forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700 to manage his release, but by that time the man had already lost considerable time in getting critical treatment, the rights panel said in a statement

police chief over reports that a man bitten by a snake lost his life as he was allegedly detained and not allowed to rush to a hospital by some policemen in Kaimur district.

The policemen had reportedly demanded Rs 2,000 in "bribe", forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700 to manage his release, but by that time the man had already lost considerable time in getting critical treatment, the rights panel said in a statement.The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim due to the "abuse of power" by police personnel who were supposed to take the man to the hospital immediately to save his life.The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that a man bitten by a snake has lost his life as he was detained and not allowed to rush to the hospital for treatment by some policemen despite his repeated request in Kaimur district".

It has issued a notice to the director general of police, government of Bihar, seeking a detailed report within two weeks. It is expected to include the status of the police investigation as well as action taken against the errant police personnel, the statement said.The Commission has also asked the district magistrate of Kaimur to inform whether any compensation has been paid to the next of kin of the deceased person, it said.According to the media report, carried on September 27, the man was bitten by a snake while he was irrigating the crops on the night on September 26.After this, he started running from the fields in a restless state towards his village. Meanwhile, a patrolling police team stopped and started interrogating him.

The man told them that he has been bitten by a snake and was running to reach home. The police personnel did not believe him and asked him to pay Rs 2,000 otherwise, he would not be allowed to move, it added.According to the news report, the police personnel accompanied him to his house but there was no money available at home. The man then called his elder brother but he also had no money with him.Somehow, Rs 700 was arranged and given to the police personnel. But by that time, reportedly, considerable time had been lost to get the snake bite victim treatment to save his life, the statement said.

NHRC Raises Concerns Over Bihar Police Detention Leading to Snake Bite Victim s Death

https://www.oneindia.com/india/nhrc-notice-bihar-police-death-snake-bite-011-3949923.html

By Krishna Kripa Updated: Tuesday, October 1, 2024, 23:06 [IST]

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken action regarding a troubling incident in Bihar. A man, bitten by a snake, reportedly died after being detained by police in Kaimur district. The NHRC has issued a notice to Bihar's police chief, demanding an explanation for the alleged misconduct that prevented the man from receiving urgent medical care.

According to reports, the man was bitten by a snake while tending to his crops on the night of September 26. In distress, he ran towards his village but was stopped by a patrolling police team. Despite his pleas for help, the officers allegedly demanded a bribe of Rs 2,000 to let him go. Unable to pay the full amount, he called his brother, who managed to gather only Rs 700.

Police Misconduct and Delayed Treatment The NHRC highlighted that if these allegations are accurate, they represent a severe violation of human rights. The police's failure to assist the man promptly could have contributed to his death. The Commission has requested a detailed report from the Director General of Police in Bihar within two weeks. This report should include the status of any investigation and actions taken against the involved officers. The NHRC's statement also mentioned that the district magistrate of Kaimur has been asked to confirm whether any compensation has been provided to the victim's family. The Commission is keen on ensuring accountability and justice for the deceased man's relatives.

Bribery Allegations and Investigation The media report dated September 27 detailed how the police allegedly accompanied the man home after stopping him. However, no money was available at his house. His brother eventually arranged Rs 700, which was handed over to the police. Unfortunately, this delay in securing funds resulted in significant time lost for obtaining critical medical treatment.

The NHRC's intervention underscores its commitment to addressing abuses of power by law enforcement. The Commission's actions aim to prevent similar incidents and ensure that those responsible are held accountable for their actions. This case highlights ongoing concerns about police conduct and accountability in India. It raises questions about how such situations are handled and stresses the importance of timely medical intervention in emergencies.

NHRC takes notice of snakebite victim's death after detention

https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/nhrc-probes-police-detention-leading-to-snakebite-victims-death-in-bihar/articleshow/113864695.cms

Oct 2, 2024, 04.34 AM IST

Patna: The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday took suo motu cognizance of media reports on the death of a snakebite victim following a delayed treatment as he was detained by some policemen, despite his repeated plea about his medical condition, in Kaimur district. The commission issued a notice to the state director general of police (DGP), seeking a detailed report within two weeks.

"It is expected that the director general of police's report will include the status of the police investigation as well as action taken against the errant personnel," the commission said, also asking the Kaimur district magistrate to inform it whether any compensation has been paid to the next of kin of the deceased person.

"As per the media reports, the policemen demanded Rs 2,000 for releasing him, forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700. But by that time he had already lost considerable time in getting the critical treatment," the commission said, observing the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim due to the abuse of power by police personnel. They were supposed to take the man to hospital immediately to save his life, it further observed.

"According to the media reports, carried last week, the victim was bitten by a snake while he was irrigating crops on the night of September 26. He started running towards home in a restless state, but a patrolling police team stopped him and started interrogating him. The man told them that he has been bitten by a snake, but the police did not believe him and asked him to pay Rs 2,000. The police accompanied him to his house but there was no money available. The man then called his elder brother, but he also had no money. By the time, Rs 700 were arranged and given to the police, considerable time reportedly was lost to get the snakebite treatment," the commission said.

We also published the following articles recently

Need safety officer for kids at all police stations: Maharashtra State Child Rights Protection Commission chiefMaharashtra State Child Rights Protection Commission president Susieben Shah emphasized the need for appointing 'child safety officers' at every police station to safeguard children's rights. Speaking at a Thane workshop, Shah called for urgent action against violations and proposed an audit of schools. Following

recent child abuse incidents, a new government resolution expands efforts for school children's safety.113714778

Police officers framed for political considerations: HCSenior counsels for IPS officers argue against registration of cases based on accused's complaints, citing potential precedent issues. Officers, accused of harassment by actress Kadambari Jethwani, seek anticipatory bail, asserting actions were lawful and politically motivated charge. Legal debate centers on prosecutorial integrity and procedure adherence. Court hearing continues Thursday.113860406

Rangpuri family death mystery: Delhi Police to conduct psychological autopsy to ascertain mental state of man, his daughtersDelhi Police plan a psychological autopsy on Heeralal Sharma and his four daughters, found dead in Rangpuri, to understand their mental state and circumstances. The father is suspected of poisoning his daughters before committing suicide. Investigators will examine medical records and family interactions to determine motivations and contributing factors.113826552

NHRC Takes Suo Motu Cognisance Of Snakebite Victim's Death Due To Treatment Delay Caused By Police Apathy In Kaimur, Bihar

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-snakebite-victims-death-due-to-treatment-delay-caused-by-police-apathy-in-kaimur-bihar

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report that a man bitten by a snake has lost his life as he was detained and not allowed to rush to the hospital for treatment by some policemen despite his repeated request in Kaimur district of Bihar.

FPJ News ServiceUpdated: Wednesday, October 02, 2024, 02:20 AM IST

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report that a man bitten by a snake has lost his life as he was detained and not allowed to rush to the hospital for treatment by some policemen despite his repeated request in Kaimur district of Bihar. Reportedly, they demanded Rs. 2000/- in bribe forcing him to call his brother in distress who could arrange only Rs 700/- to manage his release but by that time he had already lost considerable time in getting critical treatment.

The Commission has observed the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim due to the abuse of power by police personnel who were supposed to take the man to the hospital immediately to save his life. It has issued a notice to the Director General of Police, Government of Bihar calling for a detailed report within two weeks. It is expected to include the status of the police investigation as well as action taken against the errant police personnel.

The Commission has also asked the District Magistrate, Kaimur to inform whether any compensation has been paid to the next of kin of the deceased person.

According to the media report, carried on 27th September, 2024, the victim was bitten by a snake while he was irrigating the crops in the night on 26th September, 2024. After this, he started running from the fields in a restless state, towards his village. Meanwhile, a patrolling police team stopped and started interrogating him. The man told them that he has been bitten by a snake and he is running to home. The police personnel did not believe him and asked him to pay a sum of Rs. 2000/- otherwise he will not be allowed to move.

As per news report, the police personnel accompanied him to his house but there was no money available at home. The man then called his elder brother but he also had no money with him. Somehow, Rs. 700/- were arranged and given to the police personnel, but by that time, reportedly, considerable time was lost to get the snake bite victim treatment to save his life.

NHRC ने बिहार के कैमूर जिले में पुलिस कर्मियों की उदासीनता की वजह से इलाज में देरी के कारण सांप के काटने से पीड़ित की मौत की खबर का स्वतः संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-the-news-of-death-of-a-snake-bite-victim-due-to-delay-in-treatment-caused-by-the-negligence-of-police-personnel-in-kaimur-district-of-bihar/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, इसमें कहा गया है कि बिहार के कैमूर जिले में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि उसके बार-बार अनुरोध के बावजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाने दिया। कथित तौर पर उन्होंने रुपये की मांग की। 2000 रुपये की रिश्वत के लिए उसे अपने भाई को फोन किया, जो उसकी रिहाई के लिए केवल 700 रुपये का प्रबंध कर सका, लेकिन तब तक वह उपचार के लिए काफी समय गंवा चुका था।

आयोग ने कहा की यदि समाचार रिपोर्ट सत्य है, तो यह पुलिस कर्मियों के शक्ति के दुरुपयोग के कारण पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। पुलिस को उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था। आयोग ने बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पुलिस जांच की स्थिति के साथ-साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है।
आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट कैमूर से यह भी बताने को कहा है कि क्या मृतक व्यक्ति के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है।

27 सितंबर 2024 को मीडिया में आई खबर के अनुसार 26 सितंबर की रात को जब युवक खेतों में सिंचाई कर रहा था, तो उसे सांप ने डस लिया। इसके बाद वह बेचैनी की हालत में भागकर अपने गांव की ओर जाने लगा। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी। युवक ने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है और वह घर जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि 2000 रुपये दे दो, नहीं तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। खबर के अनुसार पुलिस कर्मी युवक के साथ उसके घर गए, लेकिन घर पर पैसे नहीं थे। इसके बाद युवक ने अपने बड़े भाई को फोन किया तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। किसी तरह 700 रुपये का इंतजाम कर पुलिस कर्मियों को दिया गया, लेकिन तब तक युवक को इलाज कराने और उसकी जान बचाने के लिए काफी समय बीत चुका था।

NHRC, India Open house discussion on the Rights of Children of Sex Workers and Marginalized Communities concluded with several suggestions

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-open-house-discussion-on-the-rights-of-children-of-sex-workers-and-marginalized-communities-concluded-with-several-suggestions/

By iednewsdesk On Oct 1, 2024

The Open House Discussion organized in hybrid mode by the National Human Rights Commission (NHRC), India concluded with several suggestions to ameliorate the cause of human rights of Children of Sex Workers and Marginalized Communities at its premises in New Delhi. The discussion aimed to foster a comprehensive understanding of the systemic issues at play and to generate actionable solutions for ensuring a more equitable future for all children.

Chairing the discussion, Smt. S. Vijaya Bharathi, Acting Chairperson, NHRC emphasized the need for protecting the rights of children of sex workers and marginalized communities. She highlighted India's rich cultural heritage that traditionally values the protection and empowerment of children. She also cited various constitutional provisions and laws protecting child rights. However, she said that despite several safeguards, many children still face severe challenges such as stigma, poverty, and limited access to essential resources, which perpetuate cycles of vulnerability and discrimination.

Smt. Bharathi urged collective action from policymakers, educators, and community members to create supportive environments and advocate for equitable access to education and healthcare for all children to explore their potential and aspire for a brighter future. She outlined the NHRC's critical role in ensuring the protection of rights for all including children, advocating for the assessment of current programs, and addressing gaps to promote inclusivity and equitable development for the children from the marginalized section of the society.

Before this, in his opening remarks, Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC underscored the importance of fundamental facilities, such as education and healthcare, for these vulnerable children. He emphasized the necessity of prioritizing children's health and nutrition while acknowledging the government's ongoing initiatives in this regard. He highlighted the disparities in children's rights arising from geographic and socio-economic factors and discussed efforts to enhance the education of tribal children through the Eklavya Model Residential Schools, with plans to establish one school in each block and significant funding allocated for both plain and remote areas. Despite

these advancements, he recognized the persistent challenges in improving basic services and educational opportunities for marginalized children.

He also noted the Commission's active engagement, including the Acting Chairperson's visits to various schools and childcare institutions. He remarked on the potential of technology to provide equitable educational access to children from NT/DNT communities, thereby aligning their opportunities with those available to urban children. He stressed the need for concerted efforts to bridge gaps in various indicators of child development and growth relative to the national average.

Smt. Anita Sinha, Joint Secretary, NHRC gave an overview of the open house discussion and highlighted the significant challenges the children of sex workers and marginalized communities face—such as social stigma, limited access to education and healthcare, and increased vulnerability to exploitation while emphasizing the importance of creating supportive environments for their development. She also highlighted the initiatives of the NHRC on the issues concerning the Rights of Children.

The first session explored the rights of children of sex workers and their challenges, including social stigma, lack of access to education and healthcare, and heightened vulnerability to exploitation. In the second session, the rights of children from marginalized communities were discussed, highlighting their specific needs and barriers to accessing essential services. Finally, the discussions focused on the way forward, innovative strategies and collaborative efforts among the various stakeholders—including policymakers, NGOs, and civil society organizations—to enhance the protection and promotion of these children's rights.

Some of the key suggestions that emerged during the discussions were as follows:

• There is an urgent need for empirical data, necessitating research focused on the wide range of challenges faced by the children of sex workers and children from marginalized communities along with an impact assessment of various government schemes;

• Capacity-building and sensitization programs for teachers, police officers, social workers and law enforcement officials are necessary to sensitize them to the unique backgrounds and experiences of these children, facilitating better communication and understanding;

• Proper documentation, such as Aadhar cards, should be made accessible to these sex workers and their children to facilitate their admissions to schools and the processes of obtaining their necessary identification and documentation should be streamlined;

• The government portals should mandatorily provide the mother's name instead of the father's. The option to give the name of the guardian should be added;

• Ensure proper implementation of existing schemes and laws designed to protect the rights of children of sex workers and marginalized communities;

• Developing community-based care models tailored to the unique needs of these groups is required to provide holistic support to these children;

• There is also a crucial need for the employment and active engagement of trained social workers to foster trust and facilitate access to necessary services for the children of sex workers and marginalized communities.

The Open House Discussion was attended by Shri Ajay Bhatnagar, Director General(Investigation), Shri Joginder Singh, Registrar (Law), NHRC Shri Sanjeev Kumar Chadha, Addl. Secretary, Ministry of Women and Children (MWCD), Shri Ganga Kumar Sinha, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA), Smt. Meenakshi Negi, Member Secretary, National Commission for Women (NCW), Shri Ajay Srivastava, Economic Adviser DoSJE, Ministry of Social Justice and Empowerment, Smt. Naseema Khatoon, Founder Parcham, Ms. Lalita SA, Vice President Society for Participatory Integrated Development (SPID), Mr. Prabhat Kumar, Child Protection Specialist, UNICEF, Prof. (Dr.) Asha Bajpai, Former Professor of Law Founding Dean, School of Law, Rights & Constitutional Governance, Tata Institute of Social Science, Shri Jaya Singh Thomas, Founder/General Secretary, Chaithanya Mahila Mandali (CMM), Prof. Neena Pandey, Professor, Department of Social Work, University of Delhi, Prof. (Dr.) Paromita Chattoraj, Professor of Law, National Law University, Odisha, Dr. Veerendra Mishra, (IPS) Director, Samvedna Smt. Uma Subramanian, Director, Rati Foundation, Shri Siddharth Pillai, Co-Founder Rati Foundation, Advocate Sneha Singh, Child Rights Lawyer, Shri. Ajeet Singh, Founder and Director, Guria, Prof. Jyoti Dogra, University of Delhi, Ms. Priya Krishnan, Representative from Kat-Katha, Smt. Subhasree Raptan, Programme Manager, Goran Bose Gram Bikash Kendra (GGBK), Smt. Bishakha Laskar, Secretary, Durbar Mahila Samanwaya Committee.

अनुसूचित जनजाति के 2 छात्रों की करंट लगने से हुई मौत, NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार और DGP को किया नोटिस जारी

https://ddnews.gov.in/scheduled-tribe-students-died-due-to-electric-shock-nhrc-issues-notice-to-madhya-pradesh-government-and-dgp/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के धार जिले में सरकारी छात्रावास के अधीक्षक के निर्देश पर पानी की टंकी की सफाई करते समय अनुसूचित जनजाति के 2 छात्रों की करंट लगने से मौत संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया कि यदि उस रिपोर्ट की तथ्य सामग्री सत्य है, तो इससे पीड़ित छात्रों के मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता उत्पन्न होती है। मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह की अवधि में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

छात्रावास अधीक्षक ने उनसे कथित तौर पर पानी की टंकी साफ करने को कहा था

एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के धार जिले में सरकारी छात्रावास के अधीक्षक के निर्देश पर पानी की टंकी की सफाई करते समय अनुसूचित जनजाति के दो छात्रों की करंट लगने से मौत संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि 26 सितंबर, 2024 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये छात्र टंकी की सफाई करते समय उसके भीतर पंप से जुड़े बिजली के तार के संपर्क में आ गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने उन्हें टैंक में पड़ा देखकर छात्रावास अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रावास अधिकारियों ने उन छात्रों को ऐसा खतरनाक कार्य करने के लिए कहकर बहुत ही असंवेदनशील रवैया अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई। आयोग ने पाया कि यदि उस रिपोर्ट की तथ्य सामग्री सत्य है, तो इससे पीड़ित छात्रों के मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता उत्पन्न होती है।

NHRC ने 2 सप्ताह की अवधि में विस्तृत रिपोर्ट मांगी

मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह की अवधि में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में पुलिस जांच की प्रगति की स्थिति और दोनों छात्रों के परिवारों को दी गई मुआवजा राशि, यदि कोई हो, के बारे में भी जानकारी दिये जाने की उम्मीद है।

टिल्लू ताजपुरिया केस में आधी-अधूरी रिपोर्ट से मानवाधिकार आयोग खफा

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/rampur/story-nhrc-issues-final-notice-to-jail-officials-over-gangster-tillu-tajpuria-s-murder-in-tihar-jail-201727805863957.html

रामपुर में तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने जेल अधिकारियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 22 नवंबर तक विस्तृत...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुर Tue, 1 Oct 2024 11:34 PM

। तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। आधी-अधूरी रिपोर्ट भेजने से नाराज आयोग ने दिल्ली के डीजी जेल, डीएम और डीसीपी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ आयोग में दाखिल करें अन्यथा उनके खिलाफ आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने यह कार्रवाई रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के उस पत्र पर की है, जिसमें उन्होंने आयोग से अपील की थी कि आयोग से बार-बार रिमाइंडर के बाद भी संबंधित अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं और साक्ष्य आयोग में पेश नहीं कर रहे हैं। रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल देश की अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन वहां आए दिन गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं।

आरोप लगाया कि यह सब जेल अधीक्षक और जेल प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव है। इनकी भूमिका संदिग्ध है। इसी के चलते दो मई को टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या कर दी गई।

इसके सीसीटीवी फुटेज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया था। आयोग ने दानिश खां की शिकायत पर केस दर्ज कर राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली के डीएम, राजौरी गार्डन के डीसीपी

और डीजी जेल से अब तक की कार्रवाई, जांच, पीएम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि के साथ छह सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन, रिपोर्ट आधी-अधूरी भेजी गई। जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग में दोबारा पत्र प्रेषित कर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है, इस पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में धारा 13 के तहत पूछताछ और क्रिमनल केस दर्ज करने की चेतावनी जारी की है।

तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर मामले में NHRC की सख्ती, दिल्ली के डीएम-डीसीपी को भेजे नोटिस

https://www.livehindustan.com/ncr/human-rights-commission-issued-notice-to-delhi-dm-dcp-in-gangster-tillu-tajpuria-murder-case-in-tihar-jail-201727827950747.html

मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के उस पत्र पर की है, जिसमें उन्होंने आयोग से अपील की थी कि आयोग से बार-बार रिमाइंडर के बाद भी संबंधित अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं

Wed, 2 Oct 2024 06:02 AM

दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्ती दिखाई है। आधी-अधूरी रिपोर्ट भेजने से नाराज आयोग ने दिल्ली के डीजी जेल, डीएम और डीसीपी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ आयोग में दाखिल करें अन्यथा उनके खिलाफ आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा।

मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के उस पत्र पर की है, जिसमें उन्होंने आयोग से अपील की थी कि आयोग से बार-बार रिमाइंडर के बाद भी संबंधित अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं और साक्ष्य आयोग में पेश नहीं कर रहे हैं।

रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल देश की अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन वहां आए दिन गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं। आरोप लगाया कि यह सब जेल अधीक्षक और जेल प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव है। इनकी भूमिका संदिग्ध है। इसी के चलते 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या कर दी गई। इसके सीसीटीवी फुटेज तमाम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया था।

आयोग ने दानिश खां की शिकायत पर केस दर्ज कर राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली के डीएम, राजौरी गार्डन के डीसीपी और डीजी जेल से अब तक की कार्रवाई, जांच, पीएम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि के साथ छह सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन इस मामले में रिपोर्ट आधी-अधूरी भेजी गई। इस पर शिकायतकर्ता ने आयोग में दोबारा पत्र भेज कर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। इस पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में धारा 13 के तहत पूछताछ और क्रिमनल केस दर्ज करने की चेतावनी जारी की है

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मौत पर NHRC ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-issues-notice-to-bihar-government-over-death-of-person-in-custody-3561562

2 Oct 2024 6:30 AM

New Delhi नई दिल्लीः एनएचआरसी ने मंगलवार को कहा कि उसने बिहार के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि कैमूर जिले में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और अस्पताल नहीं जाने दिए जाने के कारण सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 2,000 रुपये की "रिश्वत" मांगी थी, जिससे उसे अपने भाई को फोन करना पड़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो पुलिसकर्मियों द्वारा "शक्ति के दुरुपयोग" के कारण पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

कैमूर जिले में उसके बार-बार अनुरोध के बावजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाने दिया। एनएचआरसी ने बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि इसमें पुलिस जांच की स्थिति और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है। आयोग ने कैमूर के जिला मजिस्ट्रेट से यह भी पूछा है कि मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं। 27 सितंबर को मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, 26 सितंबर की रात को जब वह फसल की सिंचाई कर रहा था,

तो उसे सांप ने काट लिया। इसके बाद वह बेचैनी की हालत में खेतों से अपने गांव की ओर भागने लगा। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस टीम ने उसे रोका और उससे पूछताछ शुरू कर दी। व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसे सांप ने काट लिया है और वह घर जाने के लिए दौड़ रहा है। पुलिस कर्मियों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उससे 2,000 रुपये देने को कहा, अन्यथा उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पुलिसकर्मी उसके साथ उसके घर गए, लेकिन घर पर पैसे नहीं थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को फोन किया, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। किसी तरह 700 रुपये का इंतजाम करके पुलिस कर्मियों को दिए गए। लेकिन उस समय तक, कथित तौर पर, सांप के काटने वाले व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए इलाज कराने में काफी समय बर्बाद हो चुका था, बयान में कहा गया।